



सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

साप्ताहिक सूचना पत्र



दिनांक 17.10.2026 से 23.10.2026

13वाँ संस्करण

श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन
एवं शहरी कार्य मंत्री





विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1 247.29 गीगावाट की अधिकतम बिजली माँग बिना किसी कमी के पूरी
- 2 भारत और सऊदी अरब के बीच विद्युत इंटरकनेक्शन पहल तथा बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
- 3 NHPC की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की पाँचवीं 250 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू, परियोजना की क्षमता 1,250 मेगावाट पहुँची
- 4 PFC को ASSOCHAM बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र पुरस्कारों में स्वर्ण सम्मान
- 5 NPTI फरीदाबाद ने CEA अधिकारियों के लिए चार सप्ताह का विस्तारित इंडकशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया



साप्ताहिक सूचना पत्र

17.10.2026 से 23.10.2026



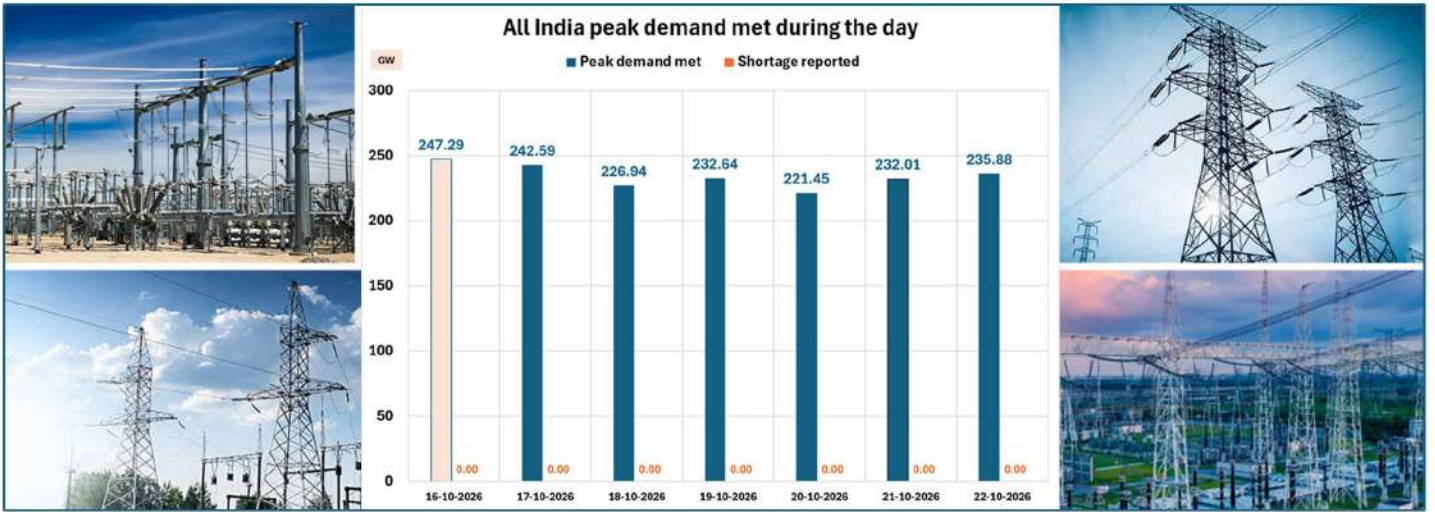
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

सत्यमेव जयते

22 अक्टूबर 2026

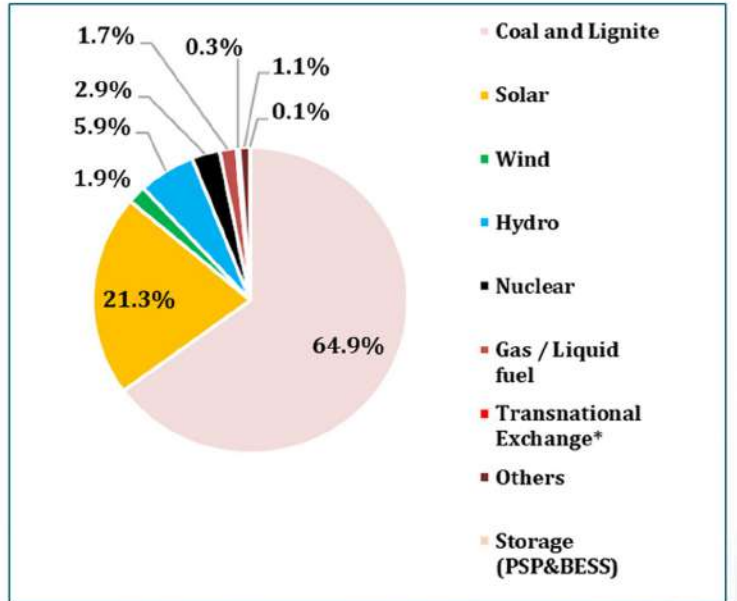
247.29 गीगावाट की अधिकतम बिजली माँग बिना किसी कमी के पूरी

नीचे दिया गया चार्ट 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक प्रतिदिन पूरी की गई अधिकतम विद्युत माँग और दर्ज की गई विद्युत कमी को दर्शाता है।



साप्ताहिक अधिकतम माँग के समय कुल विद्युत उत्पादन

Generation source	Generation (GW)	Share of Total generation (%)
Gas / Liquid fuel	4.3	1.7%
Hydro	14.7	5.9%
Nuclear	7.2	2.9%
Coal and Lignite	162.7	64.9%
Wind	4.7	1.9%
Solar	53.4	21.3%
Storage (PSP&BESS)	0.1	0.1%
Others	2.7	1.1%
Transnational Exchange*	0.8	0.3%
TOTAL	250.6	100.0%



पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर पूरी की गई अधिकतम बिजली माँग और ऊर्जा खपत में क्रमशः 17.4% और 18.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

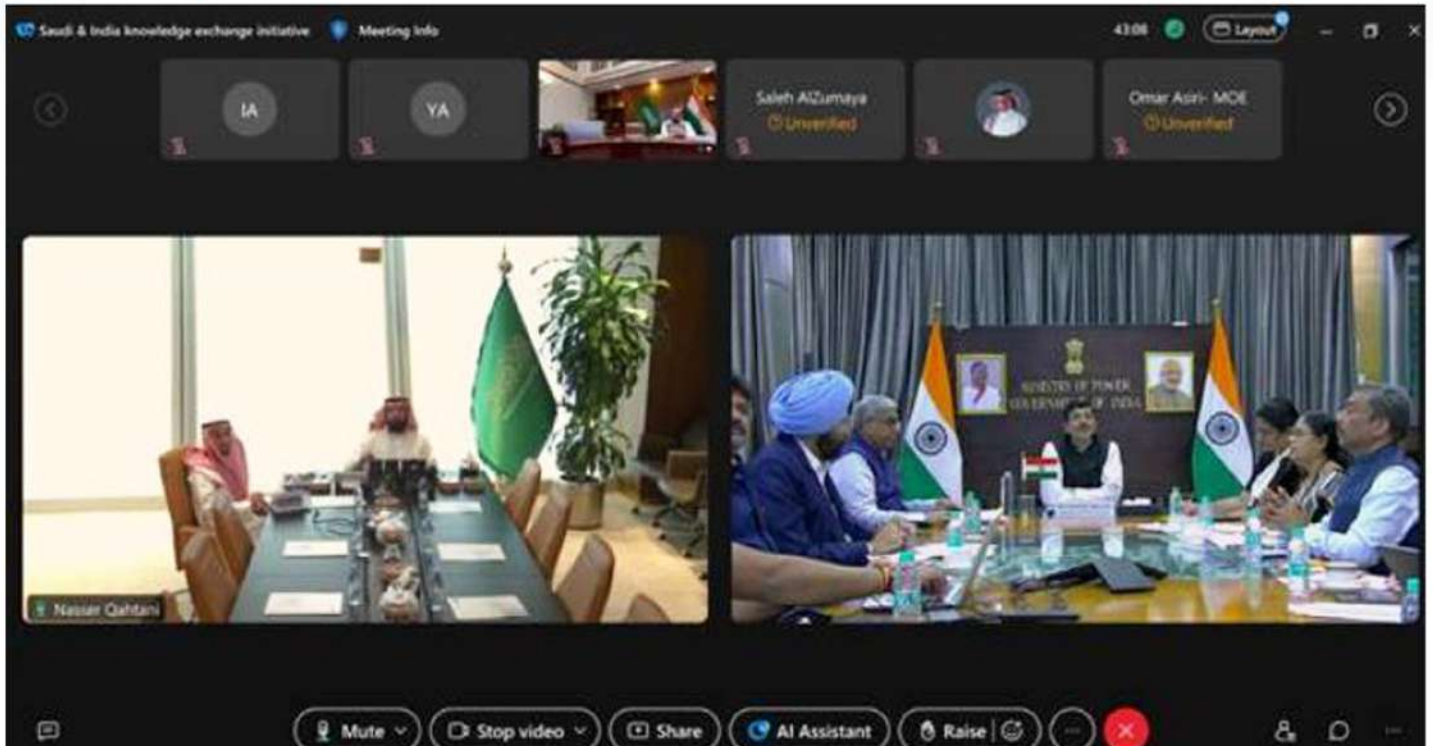
17.10.2026 से 23.10.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

19 अक्टूबर 2026

भारत और सऊदी अरब के बीच विद्युत इंटरकनेक्शन पहल तथा बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा



विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत मामलों के सहायक मंत्री महामहिम इंजीनियर नासिर अल-कहतानी के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत-सऊदी अरब विद्युत इंटरकनेक्शन पहल की प्रगति की समीक्षा की गई और बिजली क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर विचार किया गया।

चर्चा का केंद्र भारत और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित विद्युत इंटरकनेक्शन की प्रगति रही, जिसमें द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को गहरा करने की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। दोनों पक्षों ने आगे की कार्ययोजना पर विचार साझा किए और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर संवाद के महत्व पर बल दिया।

दोनों पक्षों ने बिजली क्षेत्र में आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की। इसमें तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही, भारत-सऊदी अरब बिजली साझेदारी को और मजबूत करने के लिए रचनात्मक संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

17.10.2026 से 23.10.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

23 अक्टूबर, 2026

NHPC की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की पाँचवीं 250 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू, परियोजना की क्षमता 1,250 मेगावाट पहुँची



NHPC ने अपनी 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की पाँचवीं 250 मेगावाट इकाई का वाणिज्यिक संचालन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। इस उपलब्धि के साथ परियोजना की कुल परिचालन क्षमता बढ़कर 1,250 मेगावाट हो गई है।

यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

17.10.2026 से 23.10.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

PFC को ASSOCHAM बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र पुरस्कारों में स्वर्ण सम्मान



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) को मुंबई में आयोजित ASSOCHAM के बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र ऋणदाता संस्थानों के 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस श्रेणी के अंतर्गत “समग्र प्रदर्शन (NBFCs)” वर्ग में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार ASSOCHAM के अध्यक्ष श्री निर्मल के. मिंडा ने महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा की उपस्थिति में प्रदान किया।

यह प्रतिष्ठित सम्मान बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में PFC के योगदान और भारत के बिजली क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

महत्वपूर्ण बिजली अवसंरचना के वित्तपोषण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से PFC देश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह उपलब्धि वित्तीय उत्कृष्टता तथा प्रगति को गति देने और भारत के विकास को सक्षम बनाने के PFC के मिशन की पुष्टि करती है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

17.10.2026 से 23.10.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

NPTI फरीदाबाद ने CEA अधिकारियों के लिए चार सप्ताह का विस्तारित इंडकशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया



राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (NPTI), फरीदाबाद ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के सहायक निदेशकों और उप निदेशकों के लिए चार सप्ताह के विस्तारित इंडकशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

उद्घाटन सत्र में NPTI के महानिदेशक एवं CEA के सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण) हेमंत जैन, NPTI की प्रधान निदेशक डॉ. इंदु माहेश्वरी और NPTI की निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. वत्सला शर्मा उपस्थित रहे।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए हेमंत जैन ने बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने में निरंतर सीखने, तकनीकी उत्कृष्टता और पेशेवर दक्षता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने ज्ञान को बढ़ाने, दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और ग्रिड संचालन, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी उभरती चुनौतियों के प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाएँ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवस्थित प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से CEA अधिकारियों के तकनीकी ज्ञान, पेशेवर दक्षताओं और संस्थागत समन्वय को मजबूत करना है। इसका समन्वय NPTI के उप निदेशक डॉ. के. पी. एस. परमार और सहायक निदेशक श्री अनुराग राय कर रहे हैं।

यह पहल भारतीय बिजली क्षेत्र के लिए कुशल और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार पेशेवरों को विकसित करने की NPTI की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

17.10.2026 से 23.10.2026



विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक जागरण

(23 अक्टूबर, 2026)

प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना : राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ 55.24 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, जम्मू 1 छतों पर बिजली बनाने की मुहिम में जम्मू-कश्मीर आगे

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर: बिजली बिल से रहित देने की देशव्यापी मुहिम में जम्मू-कश्मीर ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के प्रदेश ने अपने आबासीय स्फटाप सोलर लक्ष्य का 55.24 प्रतिशत हासिल कर लिया है। अब तक 46133 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जबकि 31 मार्च 2027 तक 83500 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रदेश की उपलब्धि 50.80 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हालांकि, बैंक ऋणों की मंजूरी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना



अवासीय घरों के साथ सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का अभियान जारी है • जागरण

अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस चुनौती को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सौर

ऊर्जा अभियान में दोनों संभागों की भागीदारी सामने आई है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) के क्षेत्र में 17809

स्फटाप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। जिनकी कुल क्षमता 62.69 मेगावाट है। वहीं दूसरी ओर, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) के क्षेत्र में 28324 सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनकी क्षमता 102.55 मेगावाट है। दोनों संभागों को मिलाकर आबासीय स्फटाप सोलर की कुल स्थापित क्षमता 165.24 मेगावाट पहुंच गई है।

ये आंकड़े बताते हैं कि योजना का विस्तार जम्मू और कश्मीर संभागों के बिजली वितरण क्षेत्रों में हो रहा है, न कि केवल श्रीनगर शहर में।

89 हजार से ज्यादा आवेदन : योजना के तहत 83,500 इंस्टॉलेशन के लक्ष्य

के मुकाबले 89,680 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 82,591 आवेदकों ने बैंडर का चयन कर लिया है और 69,460 उपभोक्ता समझौते पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने 42,686 स्फटाप सिस्टम के कमीशन होने की जानकारी भी दी है। आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होना योजना में लोगों की रुचि का संकेत है। हालांकि, आवेदन से लेकर सिस्टम की स्थापना और उसे चालू करने तक की प्रक्रिया पूरी करना भी उतना ही जरूरी है। यहां यह अंतर ध्यान देने योग्य है कि अधिकारियों द्वारा बताया गए 46,133 इंस्टॉलेशन और 42,686 कमीशन किए गए सिस्टम अलग-अलग आंकड़े हैं।

अमर उजाला

(21 अक्टूबर, 2026)

सौर ऊर्जा

दोनों संभाग में 47,878 संयंत्र स्थापित, कश्मीर में 60,541 तो जम्मू संभाग में 33,338 आवेदन

प्रदेश में सौर ऊर्जा से रोजाना तैयार हो रही 171 मेगावाट बिजली

राकेश शर्मा

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में सौर ऊर्जा से घरों की छतों पर रोजाना 171 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। बिजली विभाग ने दोनों संभाग में 47,878 संयंत्र स्थापित किए हैं। विभाग के पास अब तक 93,872 आवेदन पहुंच चुके हैं।

इनमें कश्मीर से 60,541 और जम्मू संभाग से 33,338 आवेदन हैं। खास बात यह है कि जिन घरों में पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत संयंत्र स्थापित किए गए हैं उनके प्रदेश में बिजली बिल शून्य हो गए हैं। बीते लगभग तीन महीनों से शून्य बिजली बिल वाले परिवारों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

इन सभी परिवारों की अब तक



346 करोड़ बतौर सस्मिडी भुगतान किया जा चुका है।

जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा कनेक्शन जम्मू जिले में लगाए गए हैं। यहां विभाग ने 10,092 कनेक्शन का लक्ष्य तय किया है। अब तक 6927 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनसे जम्मू जिले में 25.82 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है।

कटुआ जिले में 2882 कनेक्शन से 10.13 मेगावाट, किरतवाड़ में 557 कनेक्शन से 1.84 मेगावाट, उधमपुर में 1582 कनेक्शन से 5.82 मेगावाट, सांबा में 1486 कनेक्शन से 5.15 मेगावाट, रामबन में 695 कनेक्शन से 2.36 मेगावाट, मुंछ में 510 कनेक्शन से 1.56 मेगावाट, उधमपुर में 1582 कनेक्शन से 5.36

सस्मिडी के तौर पर परिवारों को हुआ अब तक

346 करोड़ का भुगतान

दोनों संभाग से विभाग के पास पहुंचे 93,872 आवेदन, कनेक्शन लेने वालों का शून्य हुआ बिल

मेगावाट, रियासी में 716 कनेक्शन से 2.36 मेगावाट और डोडा जिले में 1811 कनेक्शन से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस प्रक्रिया को 200 यूनिट मुफ्त बिजली की चुनौती घोषणा से जोड़ दिया है। हालांकि बिजली विभाग के अनुसार कश्मीर में आगामी सर्दियों के दौरान



योजना को सुचारु चलाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

विभाग ने पीएम सूर्य घर योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। नोडल अधिकारी अब तक लगाए गए कनेक्शन और उससे होने वाले बिजली उत्पादन के आंकड़े जुटा रहे हैं। योजना को पूरा करने के लिए नियोजित तरीके से काम हो रहा है और आगामी दिनों में यह संख्या बढ़ती जाएगी। -अनिल शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जेपीडीसीएल

बर्फबारी के चलते योजना की रफ्तार के धीमे होने की संभावना है जबकि जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में लगातार काम चलता रहेगा।



विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक भास्कर

(17 अक्टूबर, 2026)

भास्कर एक्सक्लूसिव मेगा प्रोजेक्ट राजस्थान की सौर ऊर्जा से रोशन होगा प्रदेश, तीन जिलों से गुजरेगी लाइन

शिवकुमार गौड़ | जीए

राजस्थान के रेगिस्तान में तैयार होने वाली सौर ऊर्जा अब हरियाणा समेत आसपास के इलाकों को रोशन करेगी। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जॉन फेज-4 (बीकानेर) से उत्पादित होने वाली सोलर बिजली की सुगम निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। करीब पांच हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस मेगा परियोजना के पूरा होने से हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में बिजली संकट से स्थायी राहत मिलेगी और लोगों को 24 घंटे निरंतर बिजली मिल सकेगी।

ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में देश भर में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हरियाणा में भी युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस पूरी परियोजना का मुख्य केंद्र भिवानी जिले का सिवानी क्षेत्र बनाया जा रहा है, जहां एक बड़ा पावरग्रिड स्थापित किया जाएगा। बीकानेर से सीधे सिवानी तक 7.65 लाख वोल्टेज (765 केवी) की अति-उच्च दाब वाली मेन ट्रांसमिशन लाइन लाई जाएगी। इसके बाद सिवानी से आगे जीए, सोनीपत, फतेहाबाद और पड़ोसी राज्य पंजाब के पाटड़ा के लिए 400 केवी यानी 4 लाख वोल्टेज की अलग-अलग लाइनें निकाली जाएंगी। इन लाइनों के सुचारु संचालन के लिए 400 केवी डबल सर्किट क्वाड कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रास्ते में आने वाले ठावरों के लिए किसानों से संवाद कर जमीन का मुआवजा तय किया जा रहा है।



तक 7.65 लाख वोल्टेज (765 केवी) की अति-उच्च दाब वाली मेन ट्रांसमिशन लाइन लाई जाएगी। इसके बाद सिवानी से आगे जीए, सोनीपत, फतेहाबाद और पड़ोसी राज्य पंजाब के पाटड़ा के लिए 400 केवी यानी 4 लाख वोल्टेज की अलग-अलग लाइनें निकाली जाएंगी। इन लाइनों के सुचारु संचालन के लिए 400 केवी डबल सर्किट क्वाड कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रास्ते में आने वाले ठावरों के लिए किसानों से संवाद कर जमीन का मुआवजा तय किया जा रहा है।

द पायनीयर

(20 अक्टूबर, 2026)

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जिले के 5 हजार 471 हितधारियों को हो रही है बिजली की बचत



पायनीयर संपादक | महाराष्ट्र
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा में जनकल्याण और आर्थिक प्रगति को हमेशा प्राथमिकता मिली है। इसी सेवा भाव को अगे बढ़ाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अमम ग्राहकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक बचत करने की दिशा में महत्वपूर्ण संचालित हो रही है। योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर सफ्टप सिस्टम स्थापित कर खर्च कम हुआ। अब उनके घर में दिनभर सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध रहती है। इससे बिजली की बचत हो रही है और परिवार का मासिक खर्च भी कम हुआ है। इसी भोज महाराष्ट्र निवासी गौतम साहू ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगने के बाद बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। पहले घर महीने बिजली बिल को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से घर की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना ने उनके परिवार को बिजली खर्च से राहत देने के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का भरोसा दिया है।

योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। महाराष्ट्र निवासी दिनेश साहू ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से उन्हें निगमित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है, जिससे परिवार को अधिक बचत बढ़ी है। इसी तरह महाराष्ट्र निवासी धनंजय जलहाड़ी ने बताया कि योजना के माध्यम से खेती पैदावार की रकम से खेती करने पर शासन से संचालित मिली, जिससे खेती का खर्च कम हुआ। अब उनके घर में दिनभर सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध रहती है। इससे बिजली की बचत हो रही है और परिवार का मासिक खर्च भी कम हुआ है। इसी भोज महाराष्ट्र निवासी गौतम साहू ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगने के बाद बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। पहले घर महीने बिजली बिल को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से घर की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि योजना ने उनके परिवार को बिजली खर्च से राहत देने के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का भरोसा दिया है।

हिन्दुस्तान

(22 अक्टूबर, 2026)

एमएमएमयूटी ग्रीन हाइड्रोजन के 50 स्टार्टअप तैयार करेगा

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नए कारोबार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आने वाले 10 वर्षों में 50 स्टार्टअप तैयार करेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को अपने आइडिया को कारोबार में बदलने का मौका मिलेगा। शुरुआती चरण में 10 स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने की तैयारी है। प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।

50 करोड़ रुपये के अनुदान से स्थापित हो रहा सेंटर फॉर एक्सिलेंस

- पहले चरण में तैयार 10 स्टार्टअप को मिलेंगे 25-25 लाख रुपये
- आईआईटी-बीएचयू के सहयोग से शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

एमएमएमयूटी में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए प्रदेश नवीन एवं



नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) 50 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे चुका है। यह केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

66 पहले चरण में 10 स्टार्टअप तैयार किए जाएंगे। इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत 25-25 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

— प्रो. अनुष्मा कोशिक शर्मा, कुलपति, एमएमएमयूटी

(आईआईटी)-बीएचयू के सहयोग से हब-एंड-स्पोक मॉडल पर स्थापित होगा। आईआईटी-बीएचयू केंद्र को तकनीकी मार्गदर्शन देगा।

प्रस्तावित केंद्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और संश्लेषण से जुड़ी तकनीकों पर शोध किया जाएगा। इसका मुख्य जोर वायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने पर रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में भी काम होगा।

केंद्र का उद्देश्य केवल शोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस क्षेत्र में नए उद्यम विकसित करने में भी मदद करना है। स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने से तकनीकी विचारों को विकसित करने और आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।



सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF **POWER**



**Office of
Manohar Lal**
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power

